



माफ न्यायालय द्वारा जारी डिडी में  
 वादी के नाम से एक कीड़ा कृषि युक्ति  
 का उल्लेख किए जाने से दूर गया है।  
~~जिस~~ विवादाधीन पत्रावली का अवलोकन  
 किया गया। मजरे कोरम जानकारी भी  
 गई। पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजों  
 के अनुसार प्रो नं 61/2013 डिडी दि  
 दिनांक 16/4/15 द्वारा जारी की गई है।  
 उपर्युक्त डिडी में यदि कोई संशोधन  
 अपेक्षित था तो वादी को रिप्लाय  
 पत्र उपलब्ध कराना चाहिए था।  
 वादी ने जिस धारा के <sup>अनुसूचित</sup> अनुतोष  
 किया है उन धाराओं के तहत डिडी  
 संशोधन किया जाना संभव नहीं  
 है। स्थिति में वादी का वाद प  
 इसी स्तर पर खारिज किया  
 है। वादी को जारी डिडी में  
 हेतु रिप्लाय पत्रावली पर अधिकांश  
 करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।  
 निर्णय मजरे ध्यान सुनाय  
 जानकर सुले न्यायालय में पुनः  
 गया।